

सं० ओ० वि०/एफ डी/17-87/9500.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० खेमका कन्टेनरज, प्रा० लि०, प्लॉट नं० 276, सेक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ब्रह्मानन्द, मार्फत अन्तर्राष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन, जी-162, इन्दरा नगर, सेक्टर 7, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ब्रह्मानन्द की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्यागपत्र दे कर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 17 मार्च, 1987

सं० ओ० वि०/एफ डी/32-87/11367.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० चारू प्रिटिंग प्रेस के 53 जी, चावला कालोनी, बल्लगढ़ के श्रमिक श्री गरीब दास, पुत्र श्री सोहन लाल मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, सेक्टर 7, गोरी कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गरीब दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/166-86/11381.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, रोहतास, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी के श्रमिक श्री चन्द्र सिंह, पुत्र श्री हरनारायण द्वारा श्री श्याम सुन्दर एडवोकेट, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतास को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित है :—

क्या श्री चन्द्र सिंह, इआईएन नं० 312/244 की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो

वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/144-86/11389.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) अधीक्षक अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भिवानी (2) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, सब-डिविजन नं० 2, भिवानी के श्रमिक श्री राजेन्द्र पाल, पुत्र श्री मेजू राम, रविदास मोहल्ला, बाल्मीकी बस्ती, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिनियम सं० 9641-1-अम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतास को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित है :—

क्या श्री राजेन्द्रपाल, सफाई कर्मचारी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?